भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2080

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाबहार पत्तन का विकास

2080. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

श्री चरनजीत सिंह चन्नी

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ईरान में चाबहार पत्तन पर शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास और संचालन में भारत की वर्तमान भागीदारी की स्थिति क्या है;

(ख) मई 2015 से मार्च 2026 तक पत्तन के विकास के लिए भारत द्वारा किए गए कुल निवेश का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रणनीतिक पत्तन के विकास में भारत की भागीदारी जारी रहेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए वर्ष 2024 में ईरान के साथ हस्ताक्षरित दस–वर्षीय समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने तथा छत्तीसगढ़ जैसे लैंडलॉक्ड राज्य से निकलने वाले वाणिज्यिक इस्पात, एल्युमिनियम और खनिज उत्पादों के लिए नए वैश्विक निर्यात बाजारों को खोलने के लिए इस व्यापार गलियारे की झमता का आकलन किया है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.) चाबहार बंदरगाह परियोजना की परिकल्पना अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ–साथ मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड

(आईपीजीएल), अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री ज़ोन (आईपीजीसीएफजेड) के माध्यम से, 2018 से बंदरगाह का संचालन कर रही है।

आईपीजीएल और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन (पीएमओ) के बीच दिनांक 13 मई, 2024 को हस्ताक्षरित मुख्य अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, भारत ने परियोजना के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा किया है। इस राशि की अंतिम किश्त अगस्त 2025 में पीएमओ को हस्तांतरित की गई थी। चूंकि चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए अमेरिका द्वारा दी गई सशर्त प्रतिबंध छूट 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो गई, सरकार इस घटनाक्रम के निहितार्थों पर विचार करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ संवाद कर रही है।

*****